



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-330/JH/1/2022-SSW

Dated: 10/07/2024

To,

श्री सुधीर के. जैन,
कुलपति,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी.एच.यू)
वाराणसी - 221005 (उ.प्र.)
(Email: vc@bhu.ac.in)
(Ph No. 0542-2369100)

Sub: बी.एच.यू. प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय के संबंध में-श्री नीरज भगत, ग्राम-चंदवे (मस्जिद के सामने), डाकघर-रांची यूनिवर्सिटी, रांची (झारखंड) का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13.06.2024 at 03:00 PM in Hotel BNR Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र/R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Ph No. 011-24641640

Copy to:-

श्री नीरज भगत
ग्राम - चंदवे (मस्जिद के सामने)
कांके रोड , पोस्ट - रांची यूनिवर्सिटी
रांची -834008

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या दिनांक 13.06.2024 को 03:00 बजे, होटल बीएनआर चाणक्य, राँची में, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की उपेक्षा एवं किए गए अन्याय के संबंध में, न्याय हेतु - श्री नीरज भगत, ग्राम-चंदवे, राँची का दिनांक 29.09.2021 का अभ्यावेदन के प्रकरण में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

F. No. NCST/SER-330/JH/1/2022-SSW

बैठक की तिथि : 13.06.2024, 03:00 बजे

प्रतिभागियों की सूची - संलग्नक

श्री नीरज भगत, ग्राम-चंदवे (मस्जिद के सामने), डाकघर-राँची यूनिवर्सिटी, राँची (झारखंड) ने अभ्यावेदन दिनांक 22.09.2021 में बताया कि वर्ष 2004 में बी.एच.यू प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ विज्ञापन संख्या 01/2003-04 (कोड संख्या-41) में सहायक रजिस्ट्रार के चयन प्रक्रिया में अन्याय किया गया। एस.टी का एक पद था, पर बताया गया कि एस.टी के पद पर कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला।

उपरोक्त प्रकरण को आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.05.2022 द्वारा उप कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University), वाराणसी को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने हेतु भेजा। बी. एच. यू प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2022 के माध्यम से तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की तथा यह बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा पद कूट - 3146 के अंतर्गत सहायक कुलसचिव अनारक्षित पद पर नियुक्तियाँ विज्ञापित पद संख्या के अतिरिक्त चयन परिणामी रिक्तियों (consequential vacancies) पर की गयी थी, न कि सहायक कुलसचिव अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर की रिक्ति के सापेक्ष। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सहायक कुलसचिव के पद पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई।

आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.07.2022 द्वारा बी. एच. यू के उपरोक्त पत्र को आवेदक को सूचनार्थ भेजा। जिस पर आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से असंतुष्टि प्रकट की। जिसे आयोग ने समसंख्यक पत्र दिनांक 13.12.2022 के माध्यम से पुनः बी. एच. यू प्रशासन को आख्या प्रस्तुत करने हेतु भेजा। परंतु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(Handwritten signature)

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

मामले का निपटान करने हेतु आयोग की माननीय सदस्या ने दिनांक 13.06.2024 को रांची में सिटिंग करने का निश्चय किया, जिसकी सूचना उप-कुलपति, बी.एच.यू. एवं आवेदक को क्रमशः सिटिंग नोटिस एवं पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा सूचित कर दिया गया।

डॉ संजय कुमार, संयुक्त कुलसचिव एवं संपर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा याचिकाकर्ता बैठक में उपस्थित हुये। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2004 में बी.एच.यू. प्रशासन के विज्ञापन संख्या 01/2003-04 (कोड संख्या-41) में सहायक रजिस्ट्रार के चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं की थीं। संयुक्त कुलसचिव ने बताया की 2004 में बची रिक्तियों को 2007 में भरा गया और विश्वविद्यालय ने सारे नियमों का पालन किया था।

संयुक्त कुलसचिव द्वारा प्रकरण में लिखित तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत नहीं कर सके और विश्वविद्यालय में अनुसूचित जन जातियों के लिए किए जा रहे विकास कार्यक्रमों, प्रशासन एवं अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित संगठनों के बीच आयोजित की जा रही बैठकों की सही जानकारी नहीं दे सके जिससे प्रतीत हुआ कि उप कुलपति महोदय ने सक्षम अधिकारी को अधिकृत नहीं किया है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा एक महीने के अंदर की गई / की जाने वाली कार्यवाई की रिपोर्ट एक महीने के अंदर प्रस्तुत करने का आग्रह किया -

- विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोग के पत्र दिनांक 13.12.2022 तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करे। यदि, समय पर आख्या नहीं मिलती है तो आयोग द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु अगली बैठक की जा सकती है, जिसमें उप-कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को 'समन' जारी किया जा सकता है।
- प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए, जैसा कि NCSA ने अगस्त, 2021 में सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सलाह दी थी (प्रति संलग्न है)
- संपर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति / जनजाति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के अनुसूचित जनजातियों / अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित संगठन के साथ आवधिक बैठके करना सुनिश्चित किया जाए। विगत वर्षों में की गई बैठकों की सूचना आयोग को प्रस्तुत करे।

काशी हिन्दू
डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2024 को 3:00 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की उपेक्षा एवं किए गए अन्याय के संबंध में, न्याय हेतु श्री नीरज भगत, ग्राम-चंदवे, रांची का दिनांक 29.09.2021 का अभ्यावेदन के प्रकरण में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

I	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
	डॉ. संजय कुमार, संपर्क अधिकारी
II	आवेदक
	श्री नीरज भगत

डॉ. आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

अलका तिवारी, भा.प्र.सं.

सचि भारत सरकार

ALKA TIWARI, I.A.S.

SECRETARY TO GOVT. OF INDIA



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

D.O.No. 18/01/NCST(IGRC)2021-Coord.

3rd August, 2021

Respected Sir,

As you are aware, the National Commission for Scheduled Tribes (the Commission) has been set up under Article 338A of the Constitution of India on 19.02.2004 and vested with the responsibility, inter-alia, to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided to the Scheduled Tribes under the Constitution or under any order of the Government and other laws for the time being in force and to evaluate the working of such safeguards.

2. Every year, the Commission receives a large number of complaints relating to service matters on issues such as (i) Non maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies, (ii) Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds, (iv) Downgrading of APARs, (v) Termination /dismissal from service, (vi) Discrimination in transfer/posting (vii) Denial of pensioner benefits etc.

3. To ensure active participation of various Government Departments in redressal of employment/service related grievances of Scheduled Tribe employees, the Commission recommends that the Departments and the Autonomous Bodies/PSUs/Attached/Subordinate offices, which are controlled by the Department should constitute an "Internal Grievance Committee". The composition of the committee may be as under:

(i)	SAG level officer of the Ministry/Department	Chairperson
(ii)	SAG/Director level officer of external Department (Scheduled Tribe)	Member
(iii)	Chief Liaison Officer/Liaison Officer (not below the rank of Deputy Secretary)	Member
(iv)	Director/Deputy Secretary level Officer (Having good knowledge of rules & procedure of Govt. of India)	Member
(v)	ST Officer of Director/Deputy Secretary/Deputy Director level (preferably lady to be nominated from other Ministry/Department incase an officer is not available within the Ministry/Department)	Member

.....2/-

(Note: In so far as Internal Grievance Committee to be set up in Autonomous Bodies /PSUs / Attached / Subordinate Offices under the Central Govt. Department is concerned, the Committee may be chaired by an Executive Director level Officer with the Chief Liaison Officer and a senior officer belonging to ST community as members).

4. The Internal Grievance Committee will examine the complaints of the employees belonging to Scheduled Tribes on matters such as (i) Non-maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies, (ii) Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds, (iv) Adverse/downgrading of APARs, (v) Termination/dismissal from services, (vi) Discrimination in transfer/posting (vii) Denial of pensioner benefits etc. and take necessary action for immediate redressal of the grievances. The Committee will prepare monthly report and submit to the Head of Organization who will monitor the action taken on the grievances and submit a quarterly report to the Commission including the reports received from the Autonomous Bodies/PSUs/Attached/Subordinate offices under the administrative control of the Department, in the format given below:

Quarterly Report for the period fromto

Sl.No.	No. of grievances registered	No. of grievances successfully redressed	No. of grievances unresolved	Action taken against wilful defaulting officer(s)	Remarks
1	2	3	4	5	6

With regards,

Yours sincerely,

A. Tiwari
(Aika Tiwari) 18/11